भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 2086

04 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

LekV fl Vh ikt DV d vrxr lMdk dk fodkl

2086. श्री तेजस्वी सूर्याः

क्या vkokl u vkj 'kgjh dk;Z मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) को इसके टेंडर एसयूआरई सड़क परियोजना के लिए स्मार्ट शहर परियोजना या कोई अन्य नीति से कोई निधि प्रदान करना चाहती है जिसे सरकार द्वारा सर्वोत्तम गैर–मोटरकृत परिवहन (एनएमटी) परियोजना का पुरस्कार दिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार टेंडर एसयूआरई परियोजना में तेजी लाने के लिए स्मार्ट शहर परियोजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार पैदल यात्री हितैषी सड़कों के विकास हेतु अन्य शहरों को प्रोत्साहित करना चाहती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): स्मार्ट शहर बेंगलूरू द्वारा यह सूचित किया गया ह कि स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत बेंगलूरू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 456.50 करोड़ रूपए की अनुमोदित लागत से 36 टेन्डर श्योर सड़कों का निर्माण रंभ किया गया ह। निधियन पद्धति के अनुसार 50% निधियन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता ह और शेष 50% निधियन कर्नाटक सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(ग): स्मार्ट सिटीज मिशन के दिशानिर्देशों में शहरों को 'वॉकेबल लौकेलटीज' सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करने की व्यवस्था ह। 19 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार, स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत पदल यात्री पथ निर्माण एवं ग-मोटर चालित परिवहन सहित संपूर्ण सड़कों पर विशेष ध्यान देते हुए 14,612 करोड़ रूपए की लागत की 329 परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी की गई हैं जिसमें से 10,421 करोड़ रूपए की लागत की 262 परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा ह/पूर्ण हो गया ह।

****